हुए तथा विश्व के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के विचार से सरकार संचार प्रणाली के विस्तार के लिए निकट भविष्य में कोई श्वेत पत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लेने का विचार रखती है;

(ख) अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में उपलब्ध टेलीफोन सुविधाओं का प्रति व्यक्ति अनुपात क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों के कौन-कौन से ब्लाक पहले ही एस०टी०डी० सेवा से जुड़े हैं और हर घर में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत में 31 मार्च,1991 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में टेलीफोनों का अनुपात प्रति 100 व्यक्ति के लिए 0.6 है जबकि अन्य विकासशील देशों जैसे ब्राजील और मलेशिया में 1 जनवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार यह अनुपात प्रति 100 व्यक्ति क्रमशः 6.01 और 8.02 है।

(ग) सभी राज्यों की राजधानियों और 427 जिला मुख्यालयों (कुल 479 में से) में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग पहले ही प्रदान की जा चुकी है। 8वीं योजना के मसौदा प्रस्तावों में टेलीफोन नेटवर्क को और अधिक सुगम बनाने पर अधिक जोर दिया गया है। प्रस्तावित उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

—सभी ग्राम पंचायतों में 1.4.95 तक फोन सुविधा प्रदान करना।

—1.4.1997 तक 1.5 लाख अतिरिक्त ग्रामों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना।

—शहरी क्षेत्रों में प्रति 100 घरों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना।

दिल्ली और मुम्बई में सड़कों के किनारे टेलीफोन बूथ

2327. **श्री रजनी रंजन साहू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मुम्बई और दिल्ली, सड़कों के किनारे टेलीफोन बूथ बनाने का विचार रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) जी हां, महानगर टेलीफोन निगम लि० पहले से ही इस प्रकार के बूथ सड़कों के किनारे तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदान करता रहा है बशर्ते कि सड़कों के किनारे इस प्रकार के बूथों के लिए स्थान उपलब्ध हो तथा इस प्रकार के बूथों पर जहां आदमी नहीं लगाए जाते, ऐसी स्थिति में उपकरणों की चोरी तथा क्षति पहुंचाने जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज

2328. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान गुजरात में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया;

(ग) 1991-92 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू किया जाना

है एवं जिनका विस्तार किया जाना है वे कहां-कहां पर स्थित हैं एवं किस प्रोद्योगिकी से संबंधित हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) पिछले वर्ष (1990-91) के दौरान गुजरात में 35 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए थे । ब्यौरे अनुपत्र-1 में दिए गए हैं। (**देखिए** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 56)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया था उनके नाम अनुपत्र-दो में दिए गए हैं। (**देखिए** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 57)

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान जिन स्थानों पर नए एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है उनके नाम तथा जिन मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जाना है उनके नाम अनुपत्र में दिए गए हैं (**देखिए** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 58)

Farmer Extension Service Scheme in Orissa

2329. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have launched a Farmers Extension Service Scheme;

(b) if so, the names of States where such scheme has been launched;

(c) whether this scheme has been launched in Orissa also; and

(d) if so, since when and the result achieved so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISRTY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) Farmers Extension Service Scheme was launched by Central Warehousing Corporation which is a public sector undertaking under the Ministry of Food.

(b) Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharshtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh and Delhi.

(c) and (d) The scheme was launched in Orissa in 1982. Since then, 208 farmers in 21 villages have been given training in the techniques of scientific storage and preservation of foodgrains.

Suggestions for functioning of Food Corporation of India

2330. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether a representation dated the 1st August, 1991 has been received by the District Manager, Food Corporation of India, Nizamabad, Andhra Pradesh, containing suggestions for full capacity utilisation of godowns and to avoid losses and to create job opportunities; and

(b) if so, the steps taken by the Food Corporation of India on the suggestions?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI: (a) Yes, Sir.

(b) FCI has reported that they do not have owned godown at Nizamabad. However, the hired godowns under ARDC scheme and CWC are being adequately utilised.

Palm Oil commercial mill in Andhra Pradesh

2331. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the palm oil commercial mill in West Godavari district of Andhra Pradesh has started production;